साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 8, अंक : 22 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 18 जनवरी 2023 से 24 जनवरी 2023 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

पर्यावरणीय चुनौतियाँ हल करेंगे ग्लोबल साउथ देश

ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताएँ ही भारत की प्राथमिकता

जी-20 में ग्लोबल साउथ एण्ड ग्लोबल गवर्नेंस फॉर लाइफ राउण्ड टेबल सम्पन्न

भोपाल

विश्व में जलवायु परिवर्तन और असंतुलन, विकास के साथ उपजी विडम्बनाएँ हैं। ग्लोबल साउथ देशों का इस असंतुलन में न के बराबर योगदान होने के बावजूद उनके द्वारा इनसे निपटने के लिये महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं। जी-20 के विशेष थिंक 20 कार्यक्रम के अंतिम दिन लोबल साउथ एण्ड ग्लोबल गवर्नेंस फॉर लाइफ राउण्ड टेबल की अध्यक्षता करते हुए मॉडरेटर और कुलपति ऋषिहुड विश्वविद्यालय सोनीपत प्रो. शोभित माथुर ने कहा कि ग्लोबल साउथ भारत की आवाज है और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताएँ भारत की प्राथमिकताएँ हैं। पर्यावरण सम्मत जीवन-शैली, नैतिक मूल्य, सुमंगलम युक्त वैश्विक सुशासन के लिये ऐसे सरल, सहज मापदण्ड होना चाहिए जो हमारे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें।

पेनलिस्ट में कार्यकारी निदेशक सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग] बांग्लादेश डॉ. फहमिदा खातून, सीनियर इन्वेस्टिगेटर नेशनल काउंसिल फॉर साइंटिफिक एण्ड टेक्निकल रिसर्च, अर्जेंटीना डॉ. ग्लेडिस लेचनी, निदेशक विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग, इंडोनेशिया डॉ. विस्नु उटोमो और लीड कोर्डिनेटर पॉलिसी ब्रिज टैंक प्रोग्राम, साउथ अफ्रीका सुश्री पामला गोपॉल शामिल थे। डॉ. खातून ने कहा कि राष्ट्रों के मध्य बने सहयोग और समन्वय से शासन के मुद्दे काफी महत्वपूर्ण हो गये हैं। सभी राष्ट्रों की आकांक्षाएँ अलग-अलग होने से आम सहमति के लिये अक्सर एक चुनौती बन जाती है। पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिये इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक कुशल पर्यावरण प्रशासन प्रणाली स्थानीय समुदायों को शामिल करती है और सभी भागीदारों के बीच समझौतों को प्रोत्साहित भी करती है। डॉ. ग्लेडिस लेचनी ने कहा कि मुख्य-धारा के अमेरिकी सिद्धांतों ने मुख्य रूप से धन के कारण लेटिन अमेरिकी विचारों और विकास की नीतियों को प्रभावित किया है। स्थानीय और दक्षिणी देशों की आवाज का निर्माण करना आज समय की आवश्यकता है। स्थानीय चुनौतियों का समाधान करने के लिये स्थानीय ज्ञान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जी-20 एक बहुपक्षीय मंच है जो इस दिशा में कार्य करता है। हमें आईपीएसए जैसे उपकरणों का उपयोग कर समाधान की ओर बढ़ना होगा। हम ऐसा नेतृत्व तैयार करना चाहते हैं, जो स्थायी उत्पादन और खपत में भी विश्वास रखता हो।

डॉ. पामला गोपॉल ने कहा कि शासन को सलाहकार सेवाएँ प्रदान करने के लिये मौजूदा ज्ञान प्रणालियों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। हमें वित्तीय बाधाओं पर नजर रखने के साथ प्रक्रिया में एक वाहक के रूप में कार्य करने की भी आवश्यकता है। अफ्रीका वैश्विक मुद्दों पर एक मुखर और जिम्मेदार आवाज के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। इसके साथ ही यह वैश्विक विकास प्रक्रियाओं में एक सक्रिय भागीदारी की भी आकांक्षा रखता है। विश्व के 55 देश में 1.4 बिलियन वाली आबादी वाला अफ्रीका वैश्विक स्तर पर मात्र 3 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन करता है। जी-20 सक्रिय जुड़ाव के लिये एक महत्वपूर्ण मंच है। भारत को अपनी अध्यक्षता से वैश्विक नैतिकता में अपना मत पुर्नस्थापित करना चाहिए।

कोरोना महामारी के बाद जीवन-शैली में परिवर्तन पर बोलते हुए डॉ. विस्नु उटोमो ने कहा कि इसने वैश्विक और आर्थिक बढ़ोत्तरी को प्रभावित किया है। पिछले 20 सालों में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण असंतुलन भी बढ़ा है। हमारी नीतियाँ, संकल्पों और तैयारियों को समाविष्ट करते हुए तैयार की जानी चाहिए। राष्ट्रों को मिल कर विश्व के तमाम ज्वलंत मुद्दों का समाधान निकालना चाहिए। पर्यावरणीय-संरक्षण के प्रति उत्तरदायी जीवन-शैली को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

सर्दी में वायु प्रदूषण के हॉटस्पॉट क्यों बन रहे हैं बिहार के शहर

मोतीहारी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक लागू होने के बाद से ही दिल्ली का वायु प्रदूषण मीडिया और आमजन के बीच बहस का केंद्र रहा है। लेकिन 2022 में मुंबई सरीखे समुद्रतटीय महानगरों तथा लचर औद्योगिक विकास और पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाले बिहार के अनेक छोटे शहरों ने खराब वायु के मामले में दिल्ली सरीखे शहरों को पीछे छोड़ दिया। हालांकि मुंबई शहर की गिरती वायु गुणवत्ता के वाजिब कारण गिनाए जा रहे हैं, जिसमें स्थानीय वाहनों, औद्योगिक उपक्रमों तथा निर्माण कार्य से निकलने वाले प्रदूषण के अलावा चक्रवात मंदौस के बाद हवा की गति का शांत हो जाना शामिल है। यहां तक की वैश्विक मौसमी परिस्थिति ला-लीना से भी इसके तार जोड़े जा रहे हैं।

मुंबई के अलावा इस साल सर्दी के मौसम की शुरुआत के साथ गंगा के मैदानी भाग में बसे उत्तर बिहार के शहरों पर वायु प्रदूषण कहर बरपा रहा है जो हेल्थ इमरजेंसी से कम नहीं है। इन छोटे शहरों की वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी (एक्यूआई 400 या उससे ऊपर) में बनी हुई है, जो स्वस्थ लोगों को भी गंभीर रूप से बीमार करने के लिए काफी है, साथ-साथ श्रम उत्पादकता को बुरी तरह प्रभावित करती है। जाड़े की शुरुआत से ही गंगा के मैदानी इलाकों के शहर वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति एक पहेली जैसी है। पहेली इसलिए भी कि बिहार का मैदानी इलाका लगभग उद्योगविहीन है और उसकी अर्थव्यवस्था केवल परम्परागत कृषि पर टिकी हुई है और यहां वायु प्रदूषण का प्रथम दृष्ट्या कोई स्रोत दिखता नहीं है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित तमाम केन्द्रीय एजेंसियां के कारणों के पड़ताल में लगी हैं और छिटपुट कयास लगाने के अलावा कोई ठोस प्रतिक्रिया आना अभी भी बाकी है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय मॉनिटरिंग नेटवर्क में बिहार के अनेकों नेटवर्क के इसी साल शामिल होने का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि मौजूदा आंकड़ों के आधार पर इस समस्या से निवारण की रणनीति में मदद मिलेगी। वायु प्रदूषण की चपेट में आए बिहार के ये अनजान से शहर वैसे पिछले साल भी कभी-कभार खबरों में आए जरूर, लेकिन कभी वायु प्रदूषण के बहस के केंद्र में नहीं आ पाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू में सर्वाधिक प्रदूषित शहरों के रूप में मोतिहारी, दरभंगा और कटिहार सरीखे शहरों के नाम का जिक्र आने के बाद गंगा के मैदानी इलाकों की इस व्यापक समस्या ने राष्ट्रीय पटल पर सभी का ध्यान खींचा। तब से लेकर अब तक पूरे प्रदेश, खासकर गंगा के मैदानी इलाकों में एक्यूआई अपने उच्चतम स्तर (गंभीर) पर बरकरार है। तब से कभी कटिहार, कभी सीवान, मोतिहारी, बेगुसराय तो कभी दरभंगा देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शुमार होते आ रहे हैं। सर्दी के साथ (नवंबर से) एक्यूआई का जो गिरना शुरू हुआ वो नए साल तक आते-आते और विकराल रूप लेता चला गया। 18 दिसम्बर को देश के दस सर्वाधिक वायु प्रदूषित शहरों की सूची में सारे के सारे शहर बिहार के थे और उसके बाद तो परिस्थितियां सुधरने के बजाय और बिगड़ी ही हैं। वहीं नववर्ष के पहले दिन के सीपीसीबी द्वारा जारी भारत के सबसे प्रदूषित 176 शहरों की सूची में ऊपर के सभी बारह शहर बिहार के थे, जहां एक्यूआई 400 के ऊपर (गंभीर श्रेणी) रिकॉर्ड किया गया। इन शहरों का वायु प्रदुषण का स्तर परम्परागत रूप से सर्वाधिक प्रदूषित दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद से कहीं अधिक, गंभीर और खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। हालांकि उसी दिन बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों के शहर बिहार के मुकाबले अपेक्षाकृत अच्छी वायु गुणवत्ता (वाराणसी-106, प्रयागराज- 165, गोरखपुर-201, लखनऊ- 264) के थे। जबकि पश्चिम बंगाल के आसनसोल (341) और सिलीगुड़ी (242) को छोड़, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आकड़ों के अनुसार, झारखण्ड के प्रमुख शहरों (रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो) में वायु प्रदूषण का आंकड़ा इस मौसम में 100 से 200 के बीच ही रहा (सीपीसीबी के मॉनिटरिंग नेटवर्क में झारखण्ड का एक ही केंद्र है)। बिहार और इससे सटे बंगाल में आश्चर्यजनक रूप से बढ़े वायु प्रदूषण के कारणों पर प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी एजेंसियां भी कयास लगाती ही दिखीं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मानव जनित निर्माण कार्य और सड़क की धूल, गाड़ियां, घर में जलाये जाने वाले लकड़ी के चूल्हों, कृषि अपशिष्ट और खुले में कचरे के जलने और औद्योगिक इकाई आदि से निकले धुएं को कारण के रूप में चिन्हित किया। इसके अलावा सर्दी में तापमान के इन्वरसन और वायु के न्यूनतम बहाव तथा भौगोलिक परिस्थितियां जैसे जलोढ़ मिट्टी, बाढ़ आदि के कारण उपजी धूल को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना। पर ये सारी स्थितियां एक्यूआई में आए सामान्य से डेढ़ से दोगुने बढ़ोतरी के लिए काफी नाकाफी जान पड़ती हैं। भारत के एक्यूआई को मापने के लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक सितंबर 2014 में नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था, जिसकी शुरुवात भारत के छह शहरों- नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद में एक सतत निगरानी प्रणाली के रूप हुई और आज इसका दायरे में देश के लगभग 210 से अधिक शहर शामिल हैं। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में छह एक्यूआइ श्रेणियां निर्धारित की हैं- अच्छा, संतोषजनक, मध्यम प्रदूषित, खराब, बहुत खराब और गंभीर। हवा में मौजूद आठ प्रमुख प्रदूषकों- पार्टिकुलेट मैटर (पीएम2.5 और पीएम10), ओजोन (ओ3), कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ), नाइट्रोजन डाईऑक्साइड (एनओ2), सल्फर डाईऑक्साइड (एसओ2), लेड (पीबी) और अमोनिया (एनएच3) के उत्सर्जन को मापकर एक्यूआई की गणना की जाती है। पीएम2.5 और पीएम10 वायु गुणवत्ता को सबसे अधिक और व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। पीएम2.5 मुख्य रूप से जलने और रासायनिक प्रक्रिया से गैस के सूक्ष्म कणों में बदल जाने से बनते हैं, वही अपेक्षाकृत बड़े कण पीएम10 यांत्रिक प्रक्रिया और टूट फुट से बनते हैं। दरअसल एक्यूआई इन आठ में से किसी एक प्रदूषक का सबसे ज्यादा वाला सबइंडेक्स वैल्यू होता है।

RBI ला रहा है कमाई का जबरदस्त तरीका, पर्यावरण बचाने के साथ कमाएं मुनाफा

नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि कुल 16,000 करोड़ रुपये का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (SGRB) दो चरणों में जारी किया जाएगा. इस निर्गम से मिली राशि को सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी परियोजनाओं में लगाया जाएगा, जो कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद करती हैं. सरल शब्दों में कहें तो ये पैसा ग्रीन इंफ्रा को बढ़ावा देने के लिए खर्च होगा. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)ने एक बयान में कहा कि पहली नीलामी 25 जनवरी को जबकि दूसरी 9 फरवरी को की जाएगी.

गौरतलब है कि आम बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी कि भारत सरकार ग्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए संसाधन जुटाने को हरित बॉन्ड जारी करेगी. इसके लिए नवंबर 2022 में एक सॉवरेन ग्रीन बांड फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया था. एक बयान में कहा गया था कि सरकार कुल 16,000 करोड़ रुपये के सॉवरेन बॉन्ड जारी करेगी.' ये ग्रीन बॉन्ड 5 साल और 10 साल की अवधि में उपलब्ध होंगे. SGRB को यूनिफॉर्म प्राइस वाली नीलामी के जरिए जारी किया जाएगा और इसकी कुल राशि का 5 फीसदी हिस्सा खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित होगी. आरबीआई ने कहा कि इन पत्रों को एसएलआर उद्देश्यों के लिए एक योग्य निवेश माना जाएगा. ये बॉन्ड द्वितीयक बाजार में कारोबार के लिए पात्र होंगे. ग्रीन बॉन्ड जारी करके जुटाई गई राशि का इस्तेमाल फॉसिल फ्यूल के उत्पादन और वितरण के लिए नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा ऐसी परियोजनाएं जहां मुख्य ऊर्जा स्रोत जीवाश्म ईंधन पर आधारित है और परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भी इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.

वर्षों से जमा कचरे के करीब 59 फीसदी हिस्से को कर लिया गया है प्रोसेस

हरियाणा हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा दायर रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि हरियाणा में वर्षों से जमा 54.18 लाख मीट्रिक टन कचरे में से करीब 31.9 लाख मीट्रिक टन कचरे यानी 58.87 फीसदी को प्रोसेस कर लिया गया है, हालांकि इसमें गुरुग्राम शामिल नहीं है।

गौरतलब है कि यह रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा 9 मई, 2022 को दिए एक आदेश पर हरियाणा की ओर से कोर्ट में दाखिल की गई है। इतना ही नहीं नगर पालिकाओं ने जानकारी दी है कि प्रोसेस किए हुए पारंपरिक कचरे के हिस्सों का वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जा रहा है। पता चला है कि प्रोसेस किए गए इस 31.9 लाख मीट्रिक टन कचरे में से करीब 29.3 लाख मीट्रिक टन संसाधित अंश जैसे कि खाद/मृदा, आरडीएफ, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट आदि में से करीब 24.38 लाख मीट्रिक टन का निपटान नगर पालिकाओं द्वारा अब तक किया जा चुका है और इससे करीब 101.05 एकड़ भूमि का पुनर्ग्रहण किया गया है। वहीं यदि 39 शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) में पैदा होते कचरे की बात करें तो उसमें भी सुधार कार्य प्रगति पर है। पता चला है कि इन स्थानीय निकायों में हर दिन करीब 2,642.45 टन कचरा पैदा हो रहा है, जिसमें से करीब 2,146 टन कचरे को हर दिन प्रोसेस किया जा रहा है और बाकी बचे कचरे को डंप साइटों पर डंप किया जा रहा है। इतना ही नहीं रिपोर्ट के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय विभाग (यूएलबीडी) ने नगर पालिकाओं में ताजा कचरे के प्रसंस्करण में जो अंतर है उसे प्रबंधित करने के लिए भिवानी, सिरसा और करनाल-कैथल-कुरुक्षेत्र के एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (आईएसडब्ल्यूएम) क्लस्टर के लिए कंसेसियनार का

चयन किया है। एनजीटी ने 12 जनवरी 2023 को एक संयुक्त समिति को निर्देश दिया है कि वो ऋषिकेश में गंगा नदी के त्रिवेणी घाट पर स्थित सीवर चैम्बर्स से होते ओवरफ्लो और उसके कारण गंगा में बढ़ते प्रदूषण की जांच करें। साथ ही अदालत ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के जिला मजिस्ट्रेट और सहायक अभियंता, गढ़वाल जल संस्थान, गंगा प्रदूषण नियंत्रण (यूनिट), ऋषिकेश को मामले की जांच करने और शिकायत सही पाए जाने पर उचित उपचारात्मक और निवारक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट के अनुसार इस मामले में एक माह के अंदर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। गौरतलब है कि देहरादून के जिलाधिकारी इस मामले में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे। लखनऊ में गांवों से निकला घरेलू सीवेज चंदे बाबा तालाब को दूषित कर रहा है। मामला लखनऊ की सरोजिनी नगर तहसील के गढ़ी चुनोती गांव का है। इस बारे में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) द्वारा एकत्र और विश्लेषण किए गए पानी के नमूनों में फीकल कॉलीफॉर्म का स्तर निर्धारित मानदंडों से ज्यादा पाया गया है, जिसके लिए मानव मल को वजह माना गया है। चंदे बाबा तालाब के कुल क्षेत्रफल के करीब एक चौथाई हिस्से में तालाब में जलकुंभी पाई गई थी, जैसा कि यूपीपीसीबी की 13 जनवरी की रिपोर्ट में कहा गया है। इस तालाब का कुल क्षेत्रफल करीब 36.909 हेक्टेयर है। साथ ही 22 सितंबर, 2022 को एनजीटी के आदेश पर संयुक्त समिति द्वारा किए निरीक्षण के समय चंदे बाबा तालाब के 36.909 हेक्टेयर क्षेत्र में से 3.1859 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थाई और अस्थाई प्राकृतिक आवासों पर अतिक्रमण पाया गया था। भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) ने एनजीटी को अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी है कि मंत्रालय सोने की जांच और हॉलमार्किंग केंद्रों के लिए पर्यावरण मानकों को निर्धारित करने के साथ उनसे होते प्रदूषण में कमी, नियंत्रण और रोकथाम के लिए नीति तैयार करने में लगा हुआ है। गौरतलब है कि इन मानकों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के माध्यम से लागू किया जाता है। एसपीसीबी/पीसीसी को इन मानकों को लागू करने और उद्योगों द्वारा इनका पालन किया जा रहा है इसपर निगरानी करने की जरूरत है। गौरतलब है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पीसीसी को ऐसे सभी उपाय करने के लिए अधिकार दिए गए हैं जो पर्यावरण की सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कमी के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन समझे जाते हैं। किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में इनकी स्थापना या संचालन के लिए सहमति जारी करना संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पीसीसी के अधिकार क्षेत्र में आता है और उन्हें अपने संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए एमओईएफएंडसीसी द्वारा अधिसूचित मानकों की तुलना में कहीं अधिक कड़े उपायों को अपनाने का अधिकार है।

इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए एक नियामक संस्था की जरूरत-सीएसई

नई दिल्ली। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को लोकप्रिय बनाने के लिए देश में दिए जा रहे विभिन्न प्रोत्साहनों के बावजूद देश में पंजीकृत नए वाहनों की कुल संख्या में इन वाहनों की हिस्सेदारी 4.72 प्रतिशत ही है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के द्वारा जारी एक नए आकलन में कहा गया है कि वाहन उद्योग को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे वाहनों की कुल बिक्री और उत्पादन में शून्य उत्सर्जन वाहनों (जेडईवी) का कितना हिस्सा होगा, इसके लिए नियामक आदेश की तत्काल जरूरत है।

राष्ट्रीय राजधानी के निकट ग्रेटर नोएडा में 15 जनवरी, 2023 से वार्षिक ऑटो एक्सपो शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम में कई नए इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किए गए, जिनमें एक सौर ऊर्जा वाली कार, एक तीन-पहिया पावरट्रेन किट और सैन्य उपयोगिता वाले वाहन शामिल हैं। सीएसई द्वारा एक परामर्श बैठक आयोजित की गई, इसमें वाहन उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों ने इस बात पर सहमति जताई कि इलेक्ट्रिक वाहनों को आगे बढ़ाने के लिए एक नियामक आदेश की जरूरत है। बैठक में वाहन उद्योग के प्रतिनिधियों के अलावा सरकारी अधिकारी एवं तकनीकी समूह से जुड़े लोग भी शामिल थे। सीएसई की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि दोपहिया और तिपहिया वाहनों, कारों और बसों जैसे अलग-अलग चीजों से जुड़े प्रतिनिधियों ने जेडईवी नियम को लागू करने की संभावना के बारे में अलग और सशर्त विचार किया। हालांकि, बैठक में सभी ने इस रणनीति का समर्थन किया। एक ऐसा नियम जो लंबे समय के लिए बनी नीति में झलकती हो और यह निवेश तथा बाजारों में अधिक स्थिरता ला सकता है। सीएसई की कार्यकारी निदेशक (रिसर्च एंड एडवोकेसी) अनुमिता रॉयचौधरी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए उपभोक्ताओं और फ्लीट ऑपरेटरों के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जैसे कि केंद्रीय योजना (हाइब्रिड) इलेक्ट्रिक वाहनों (फेम द्वितीय) का फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग और राज्य सरकारों की ईवी नीतियां, जेडईवी नियम के अतिरिक्त असर डालने वाले साधनों की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि नियम के अंतर्गत निर्माताओं को जेडईवी की कम से कम तय की गई संख्या बेचनी होगी, क्योंकि शून्य उत्सर्जन को आगे बढ़ाने के लिए बाजार में उनकी कुल बिक्री हिस्सेदारी आवश्यक है। भारत ने जो लक्ष्य रखे हैं उनमें मंत्रिस्तरीय घोषणाओं में 2030 तक 30 प्रतिशत विद्युतीकरण करना, थिंकटैंक नीति आयोग का 2030 तक दोपहिया और तिपहिया बाजारों में 70 से 80 प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य को हासिल करना। भारत की वैश्विक घोषणा जिसमें कहा गया है कि 2030-2040 तक वाहनों में 100 प्रतिशत बदलाव कर शून्य उत्सर्जन वाहन (जेडईवी) को अपनाना, जिसमें दोपहिया और तिपहिया वाहनों का विशेष उल्लेख किया गया है। मूल्यांकन के लिए खुदरा उपभोक्ता सर्वेक्षण के अलावा सीएसई ने शहरी परिवहन विशेषज्ञों और राज्य परिवहन निगमों के साथ बातचीत की। एक जेडईवी को अपनाने के लिए तेजी से बाजारों और मूल्य प्रवृत्तियों का आकलन और जेडईवी संबंधी नियम आदेश और ईंधन की कीमतों, नियमों जैसे नीतिगत उपकरणों की समीक्षा ने इसका समर्थन किया है। वाहन डेटाबेस से पता चलता है कि नए वाहन पंजीकरण में ईवीएस की हिस्सेदारी खासकर दोपहिया और तिपहिया वाहनों में काफी बढ़ी है। चुनौती का अगला स्तर सभी वाहन संबंधी अनुभागों में विद्युतीकरण का विस्तार करना है। सीएसई के मुताबिक, फेम द्वितीय के तहत निर्धारित लक्ष्यों को अभी पूरी तरह से हासिल नहीं किया जा सका है। 10,000 के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 6,630 ई-दोपहिया वाहन, दिसंबर 2022 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, 55,000 के लक्ष्य के मुकाबले 5,375 व्यावसायिक ई-चार पहिया और 7,000 के मुकाबले 3,738 बसों को मंजूरी दी गई है। रॉयचौधरी ने कहा कि इंटरनल कंबशन (आईसीई) वाहनों के साथ ईवी मॉडल की कीमत समानता में दोपहिया और तिपहिया वाहनों के सेगमेंट में काफी सुधार हुआ है।

बिजली बिल दे सकता है 'झटका', पर्यावरण बचाने को सरकार ने बदली प्लानिंग

नई दिल्ली. आने वाले समय में बिजली उपभोक्ताओं का खर्च बढ़ सकता है. कोयले की ढुलाई के खर्च में इजाफा होने की वजह से बिजली कंपनियां आने वाले समय में इलेक्ट्रिसिटी रेट में वृद्धि कर सकती है. हाल ही में केंद्र सरकार ने फैसला लिया था कि एनटीपीसी समेत देश के कई राज्यों को कोयले का ट्रांसपोर्ट रेल और समुद्र के मिले जुले तरीकों से करना होगा. नए रेल-शिप-रेल मैकेनिज्म से पावर प्लांट की बिजली बनाने की लागत में 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है.

एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर कोयले की जरूरत के पांचवें हिस्से का परिवहन भी नए तरीके से किया जाएगा तो पावर प्लांट की लागत बढ़ सकती है. अगर इस लागत का हिस्सा ग्राहकों पर डालने का फैसला लिया जाता है तो संभव है आपको पहले से ज्यादा बिल चुकाना पड़ेगा. केंद्र सरकार ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि फैसले से सालाना उस पर 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. पंजाब ने मांग की है कि उसे पूरा कोयला रेल मार्ग से पाने की छूट दी जाए. हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय ने गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और एनटीपीसी को कहा है कि वो अपनी जरूरत के कोयले में से कुछ हिस्से का ट्रांसपोर्ट रेल-शिप-रेल मोड से करें. इस तरीके से पहले खदानों से कोयला रेल के जरिए नजदीकी बंदरगाह तक पहुंचाया जाता है फिर समुद्री रास्ते से कोयला पावर प्लांट के नजदीकी बंदरगाह तक पहुंचता है. फिर वहां से रेल के द्वारा ही कोयला पावर प्लांट में पहुंचाया जाता है. देश में कोयले को मुख्य रूप से रेल और सड़क मार्ग से ही देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भेजा जाता है. सड़क मार्ग से कोयले के परिवहन में कई दिक्कतें और जाखिम हैं. सड़क मार्ग से कोयला भेजने से जहां दुर्घटनाएं होती हैं, वहीं पर्यावरण प्रदूषण भी ज्यादा होता है. कई जगह सड़कें काफी संकरी हैं, इससे कोयले की ढुलाई में ज्यादा समय भी लगता है.

भूस्खलन के बाद बदल दी पहाड़ की तस्वीर

उत्तरकाशी जोशीमठ में आई दरारें और भू धंसाव की समस्या के बीच ए?क नई बहस छिड़ गई है। जिसमें पहाड़ों को बचाने और इस तरह की समस्या से बचाव के लिए वृक्षारोपण पर जोर दिया जा रहा है। जिसके लिए उत्तरकाशी का उदाहरण दिया जा रहा है। 2003 में वरुणावत पर्वत से भूस्खलन हुआ, जिसने उत्तरकाशी शहर की पूरी तस्वीर ही बदल दी थी। तब अकेले वरुणावत पर्वत के ट्रीटमेंट पर करीब 70 करोड़ पैसा खर्च किया गया। इसके अलावा विस्थापन और अन्य कार्यों पर करोड़ों रुपए पैसे की तरह बहा दिए गए। लेकिन इस आपदा से सीख लेते हुए उत्तरकाशी के एक पर्यावरण प्रेमी ने दिन रात मेहनत कर सबके सामने मिसाल पेश की, जो कि अब जोशीमठ प्रकरण के सामने आने के बाद फिर से चर्चा में हैं।

उत्तरकाशी के जिस इलाके में भू धंसाव और आपदा आई थी, वहीं पर आज प्रताप सिंह पोखरियाल का श्याम स्मृति वन है। जो कि 40 हेक्टेअर में तैयार किया हुआ है। पोखरियाल ने बताया कि इसमें 4 से 5 लाख पेड़ पौधे हैं। जिसमें वनस्पतियों से लेकर सभी तरह की जड़ी बूटी और अन्य पौधे रोपे गए हैं। श्याम स्मृति वन अब स्थानीय लोगों के लिए जहां एक दर्शनीय स्थल बन गया है, वहीं छात्रों और पर्यावरण से जुड़े लोगों के लिए एक रिसर्च सेंटर बना हुआ है। बता दें कि तब उत्तरकाशी शहर के विस्थापन की भी मांग उठी थी। लेकिन वरुणावत का ट्रीटमेंट होने के बाद शहर को बचाया जा सका। श्याम स्मृति वन के संस्थापक प्रताप सिंह पोखरियाल एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने वरूणावत पर्वत के भू-धंसाव वाले हिस्से पर वृहद स्तर पर वृक्षारोपण करके मिसाल कायम की है। वहीं इन्होंने अपने निजी प्रयासों से बगैर किसी सरकारी धन की सहायता के जनपद के अन्य हिस्सों में भी 5 हरे-भरे वन और 21 हर्बल गार्डन तैयार किये हैं। प्रताप ने अपने जीवन के तैंतालीस वर्ष प्रकृति संरक्षण के लिए समर्पित किए हैं वे लोगों के लिए प्रेरणादायी बने हुए हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 में अपने वनों से हजारों लीटर गिलोय काढ़े व ग्रीन टी के निशुल्क वितरण के लिए खासे चर्चित रहे हैं। जिसमें शिक्षक शंभू प्रसाद नौटियाल और समाजसेवी सुभाष चंद्र नौटियाल भी उनके साथ जुड़कर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं।

पर्यावरण से स्वस्थ रहने का दिया लोगो को संदेश

मुंबई बोहरा समुदाय के टोलोबा उल कुलियात इल मुमेनिन मुंब्रा की और से 15 जनवरी रविवार को 40 किलोमीटर की साइकिल रैली का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य मुंब्रा वासियों के बीच एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्लास्टिक, स्वाथ्य, प्रदूषण आदि के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। मुंब्रा बोहरा समाज से वरिष्ठ आमिल शेख गुलाम अब्बास व पूर्व स्थानिय नगरसेवक राजन कीणे द्वारा हरी झंडी दिखाकर निकाली गई रैली में करीब 80 युवा और वृद्धों सहित साइकिल चालकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के आयोजकों में से एक, अलीअसगर रामपुरावाला ने कहा, %इस कार्यक्रम को करने का पूरा विचार और उद्देश्य सभी को दैनिक आधार पर साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित करना स्वाथ्य, प्रदूषण और यदि संभव हो तो आसपास परिसर में साइकिल से काम पर जाना भी।%

इस साइकलिंग रैली अपने 40 किमी के मार्ग पर, साइकिल सवार आनंद कोलीवाड़ा से मुख्य सड़क होते हुए एमएम वैली, रेती बंदर, खारेगाव टोल नाका होते हुए आनंद कोलीवाड़ा तक संपन्न हुआ। कहा कि टोलोबा ने यह जनहित कार्यक्रम समुदाय की वैश्विक परियोजना पहल के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया जो पर्यावरण, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य और जल सुरक्षा, शिक्षा और स्वच्छता के क्षेत्र में काम करता है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादकः डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008